श्रीमती शान्ति पहाड़िया : श्रीमन, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो पेड़ लगाए जाते हैं क्या उनके लिए कोई समय सीमा रखी जाती है कि इतने समय बाद काटे जाएं दूसरी बात यह है कि सड़क किनारे पेड़ लगाए जाते हैं या दूसरी जगह लगाए जाते हैं जहां कि बहुत जमीन खुली पड़ी है, वहां फलदार वृक्ष भी लगाए जाएं जिससे कि फल भी मिलें, लकड़ी भी मिले और छाया भी मिले । तो क्या मंत्री जी पेड़ों की समय सीमा के बारे में ख्याल रखेंगे क्योंकि उतने लगाए नहीं जाते जितने कि काटे जाते हैं । वे बेचारे बड़े भी नहीं हो पाते ।

श्री जैड० आर० अन्सारी : सर यही एक जवाब है जो मैं देना चाहता हूं । जहां तक हमारे पास इनफार्मेशन है, उसके अनुसार डि-फारेस्टेशन का रेट 1.3 मिलियन हैक्टेयर एवरी इयर है और एफारेस्टेशन का 2 मिलियन हैक्टेयर एवरी इयर की हमारी उपलब्धि है । दूसरे जहां तक माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि उस प्लांटेशन में फलदार वृक्षों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए । मैं बताना चाहूंगा कि हमने कुछ नए डिसीजंस लिए हैं । एक डिसीजन यह है कि हमने एक तरह के वृक्ष लगाने को रोका है, मना किया है और जो वेस्ट लैंड डवलपमेंट का कार्य है जिसमें कि मेनली एफारेस्टेशन का कार्य करना है, उसमें हम लोकल पापुलेशन को कंसल्ट करते हैं कि कितने फोडर की जरूरत होगी, कितनी टिम्बर की जरूरत है और कितनी फ्यूल वुड की जरूरत है । अलग-अलग किस्मों के वृक्ष लगाए जाएं जिससे कि उससे लोकल कम्यूनिटी फायदा उठा सके, इस बात का हम ध्यान रखते हैं ।

MR. CHAIRMAN: Question No. 150. (*Interruptions*)

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: I have raised my hand for long. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No, the Question Hour is not a special mention hour. ...(*Interruption*)... This is my discretion. I have got a list. You cannot question my authority.

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: I am not questioning your authority.

MR. CHAIRMAN: That is all. I have called the next question.

श्री राम चन्द्र विकल : सभापति महोदय हम शुरू में हाथ उठाते हैं, लेकिन आप हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं । मुझे चार दिन हो गए हाथ उठाते हुए, आप देखते नहीं हैं ।

ठाकुर जगतपाल सिंह : बैठ जाइए विकल जी ।

मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता

*150. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :†

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1989–90 और 1990–91 के दौरान मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत कोई नये क्षेत्र शामिल करने का विचार रखती हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है या दी जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है । राज्य सरकारों से वर्ष 1989–90 और 1990–91 के दौरान कार्यक्रम

†सभा में यह प्रश्न ठाकुर जगतपाल सिंह द्वारा पूछा गया ।

के अन्तर्गत नए क्षेत्रों को शामिल किए जाने का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सभापति : प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Communal riots in the country

*141. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of incidents of communal riots in the country during the last three years, yearwise and Statewise;

(b) what is the number of persons killed and injured in these incidents, yearwise and Statewise; and

(c) what steps are being taken by the Central Government to curb such incidents?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b) The required information is detailed in the Annexure [*See* Appendix CLI, Annexure No. 75]

(c) Material support in terms of para-military forces and equipment is provided to the State Governments as and when occasion arises or demands are made to assist them in effectively managing and controlling the riot situation on the ground. Further, the Central Government has circulated a set of guidelines to the State Governments to help them manage communal violence and restore and reinforce communal harmony. Among these are the guidelines for preventing and controlling communal violence, the guidelines for processions and for relief and rehabilitation measures.

2. Apart from above, from time to time, the National Integration Council has been deliberating on the long terms measures for strengthening secularism in our society. The report of the Standing Committee of the National Integration Council has been commended to the State Governments.

3. Lessons have been drawn from the recent riots e.g. the Meerut riots of 1987 and based upon those, a fresh set of guidelines was circulated to the State Governments on 26th February, 1988.

4. In view of the happenings in Punjab and other parts of the country, the question of prevention of missuse of religious institutions for political and illegal purposes as also in the context of separation of religion from politics, the need was felt to check this misuse immediately and accordingly the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Ordinance, 1988 was promulgated on 26th May, 1988. Subsequently, a Bill to replace this Ordinance was introduced in the Monsoon Session of Parliament which was enacted on 2nd September, 1988.

Foreign exchange reserves

*142. SHRI ANAND SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the position of foreign exchange reserves as on the 30th June, 1989; and

(b) what steps are proposed to be taken to further improve the balance of payments position?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) The foreign exchange reserve as on 30th June, 1989 stood at Rs. 6075 crores (excluding Gold & SDRs)